Title: Need to set up a Rashtriya Gramin Bank in the Public Sector for the benefit of rural people. – Laid.

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी):अध्यक्ष महोदय, देश की समस्त 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकृत एवं केन्द्रीयकृत परिचालन एवं निर्देशन हेतु वर्तमान में चल रही 28 प्रवर्तक बैंकों की व्यवस्था समाप्त की जाये, जिसमें प्राइवेट बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक भी शामिल हैं। संचालन हेतु 28 प्रवर्तक बैंकों के होने से एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 28 विभिन्न प्रकार की व्यवस्था एवं नियम कानूनों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे एकीकृत परिचालन पूर्णतः बाधित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपरोक्त 28 स्वामित्व वाले प्रवर्तक बैंक ही ग्रामीण भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी है जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति में एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सबसे बड़े बाधक बनकर सामने आए हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्रीय स्तर पर भारतीय राट्रीय बैंक के नाम से एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था स्थापित की जाये अथवा जोनल या राज्य स्तरीय बैंक की स्थापना की जाये, जिसका संचालन नाबार्ड या कोई भी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था या होल्डिंग कम्पनी के अधीन हो, जिसमें भारत सरकार की अंशधारिता 50 प्रतिशत पूंजी नाबार्ड/वित्तीय संस्था/होल्डिंग कम्पनी के पास हो।